MOTION FOR ELECTION TO THE COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI O. RAJAGOPAL): Sir, I move the following motion:-

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate one Member from Rajya Sabha to associate with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Shri N. Thalavai Sundaram, resigned from the membership of Rajya Sabha and resolves that the House do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, one Member from among the Members of the House to serve on the said Committee."

The question was put and the motion was adopted.

REPLY TO THE DISCUSSION ON THE STATEMENT OF PRIME MINISTER RECENT SUMMIT-LEVEL TALKS HELD BETWEEN INDIA AND PAKISTAN IN AGRA.

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : सभापति जी, 24 जुलाई को भारत-पाक वार्ता के बारे में मैंने एक वक्तव्य दिया था। वक्तव्य एक महत्वपूर्ण विषय से संबंधित था इसलिए यह स्वाभाविक है, सचमुच में आवश्यक था कि उस पर विस्तार से चर्चा होती और भारत-पाक संबंधों के बारे में हम निश्चित रूप से कुछ फैसले कर सकते।

आगरा वार्ता हमारी दृष्टि से एक सिलसिला था। यह सिलसिला लाहौर से चल रहा है। उस समय भी यह सरकार थी। जितनी तैयारी आगरा के बारे में की गई थी उतनी तैयारी लाहौर वार्ता के पहले हुई थी। लेकिन दोनों में एक अंतर रहा कि बीच में पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो गया। अब पाकिस्तान की सत्ता जिनके हाथों में केंद्रित है, वे लाहौर को हृदय से स्वीकार करना नहीं चाहते। इतना ही नहीं वे शिमला समझौते के बारे में भी एक अनमना रवैया अपनाते हैं। इस सत्ता परिवर्तन के कारण और बीच में कारगिल युद्ध हुआ, एक ऐसी खाई पैदा हो गई, जिसके कारण विश्वास का संकट उत्पन्न हुआ। हमारे लिए आगरा वार्ता एक कड़ी थी। हमने उसी दृष्टि से तैयारी की थी। हम समझते थे कि पाकिस्तान भी इस बात को समझेगा और कारगिल के युद्ध से जहां सूत्र टूट गया है उस सूत्र को फिर से कायम करेगा।

यह देखकर संतोष हुआ है कि जिन 22 राज्य सभा सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और जिन में विदेश मंत्री जी भी शामिल हैं उन्होंने, वार्ता चलनी चाहिए, इस बात पर जोर दिया। यह